स्थिति इसके विपरीत है। गांवों, कस्बो और शहरों की स्थिति भी कृषि-उत्पादन अधिक करने वाले प्रदेशों की अच्छी है। स्कूल और कालेज भी वहीं अधिक हैं। हमारे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना जनता की सर्वांगीण उन्नति का साधन है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे सुगम तरीका उत्पादन का उचित मूल्य मिलना है। अब के किसानो के गेहूं का सरकार ने मूल्य कम नियत किया। कृषि वैज्ञानिकों न गेहूं की लागत 211 रुपये प्रति क्विंटल बताई थी। मूल्य नियत किया 151 रुपये।

किसान विचार कर रहा है कि गेहूं के स्थान पर उन फसलों को बोए जिन का मूल्य अधिक मिलता है। गेहूं का उत्पादन कम होने से हमें गेहूं का बाहर से आयात करना पड़ेगा। राष्ट्र की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों कम होगी। कृषि मंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते। अत: माननीया प्रधान मत्री से प्रार्थना है कि गेहूं के मूल्य की गेहूं की बुआई से पहले घोषणा कर दें और वह 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिये।

15.05 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW : *in the Chair*]

(v) TRANSPORT ARRANGEMENTS IN THE HILLY REGIONS

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में परिवहन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति अत्यधिक असन्तोषजनक है। नए मोटर मार्गों के खुलने से जहां अधिक बसों की मांग है, वहीं पुरानी जर्जर बसों के चलने से बस दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। इस क्षेत्र के पिथौरागढ़ जनपद में विगत दो वर्षों के अन्तराल में 200 से अधिक व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने से अकाल काल-कवलित हुए हैं। कुछ ही दिनों पूर्व यहां एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 26 व्यक्ति मरे हैं। इस सबके फलस्वरूप यहाँ भयंकर असन्तोष व रोष व्याप्त है। केन्द्रीय परिवहन अधिकरण को शीघ्र निम्न कदम उठाने के लिए राज्य के परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों तथा सीमा सड़क संगठन के लोगों को सलाह देनी चाहिए :—

1. इस क्षेत्र के समस्त मोटर मार्गों पर राज्य परिवहन निगम तथा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा संचालित बस सेवाओं को समानान्तर रूप से चलने देने की अनुमति राज्य सरकार को देनी चाहिये। प्रतियोगिता के कारण दोनों संगठन अच्छी सेवा उपलब्ध करवाने की चेष्टा करेंगे।

2. पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे चैसिस की बसें चलाई जानी चाहियें।

3. इन क्षेत्रों में किसी भी ऐसी बस को नहीं चलाया जाना चाहिये जो कि 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हो।

4. यहाँ प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर बस-डिपो व वर्कशाप खोले जाने चाहियें।

5. पिथौरागढ़ जैसे सीमान्त जनपद में क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय शीघ्र खोला जाना चाहिये।

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग और बार्डर रोड संगठन को कहा जाना चाहिये कि वे वर्तमान मोटर मार्गों को और अधिक चौड़ा व सुविधायुक्त बनावें।

7. इन क्षेत्रों में चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं उनकी शारीरिक स्वस्थता बनी रहे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

8. बस चालकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये ।

9 उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को 4 भागों में विभक्त किया जाना आवश्यक है, तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक पृथक् परिवहन निगम बनाया जाना चाहिये ।

(vi) NEED TO ESTABLISH A POWERFUL T.V. STATION IN JABALPUR (MADHYA PRADESH)

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष का मध्य बिन्दु जबलपुर जिला है । परकीय आक्रमण की दृष्टि से अत्यन्त सुरक्षित स्थान है, इस रूप में अंग्रेजों ने इसका उपयोग किया तथा अनेकों सुरक्षा संस्थानों की स्थापना की । स्वतंत्रता के पश्चात् इस कड़ी में, भारत शासन द्वारा व्हीकल फैक्टरी का निर्माण किया गया । आज लगभग एक लाख कर्मचारी इन सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत हैं । थल सेना के अनेकों प्रशिक्षण संस्थान तथा पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ के भी प्रशिक्षण संस्थान तथा फैक्टरी यहां पर कार्यरत हैं ।

जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का यह दूसरा शहर है । मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय भी जबलपुर में स्थित है । शिक्षा की दृष्टि से जबलपुर अत्यन्त महत्वपूर्ण है । आज यहां दो विश्वविद्यालय हैं तथा लगभग एक लाख विद्यार्थी इस संस्कारधानी में अभ्यासरत रहते हैं । आकाशवाणी की सुविधा भी यहां उपलब्ध है ।

मध्यप्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से छोटे स्थान भोपाल तथा रायपुर को टी०वी० की सुविधा पहले से ही उपलब्ध हो चुकी है, परन्तु जबलपुर अभी तक वंचित है ।

ज्ञात हुआ है कि भारत शासन द्वारा निकट भविष्य में टी०वी० के विस्तार की योजना बनाई है तथा जनसंख्या में जबलपुर से छोटे तथा कम महत्व के नगरों का समावेश इसमें किया गया है, परन्तु जबलपुर को इस योजना से दूर रखा गया है ।

यदि जबलपुर में टी. वी. की स्थापना की जाये तो सिर्फ जबलपुर जिले को ही नहीं अपितु लगे हुए मण्डला, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह तथा सतना जिलों को भी इसका लाभ मिल सकेगा । लगभग चालीस लाख जनता जिसमें बहुत बड़ी संख्या आदिवासियों की है, प्रभावित होगी ।

अतएव भारत शासन से अनुरोध है कि जबलपुर को भी आगामी विस्तार योजना में सम्मिलित कर 2 अक्तूबर, 1983 (गांधी जयन्ती) से हाई पावर टी. वी का शुभारम्भ किया जाये ।

———

STATUTORY RESOLUTION RE-DISAPPROVAL OF SOCIETIES REGISTRATION (DELHI AMENDMENT) ORDINANCE

AND

SOCIETIES REGISTRATION (DELHI AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: Now the House shall take up item no. 8 (Statutory Resolution) and item no. 9 together. Shri Shejwalkar.

SHRI N.K. SHEJWALKAR (Gwalior) : I beg to move the following resolution :-